[2020] 12 एससीआर 279

शांति देवी उर्फ शांति मिश्रा बनाम भारत संघ और अन्य।

(2020 की सिविल अपील संख्या 3630)

05 नवंबर, 2020

[अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और

एम. आर. शाह, जे.जे.]

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226 - सिविल प्रक्रिया संहिता - धारा 20 - कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 - पारिवारिक कोयला खान पेंशन योजना, 1998 - क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार - सरकार ने एक परिवार कोयला खान पेंशन योजना, 1998 दिनांक 05.03.1998 को अधिसूचित किया - इससे पहले, अपीलकर्ता के दिवंगत पति ने उक्त पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था - हालांकि, बाद में अपीलकर्ता के पति ने दिनांक 09.01.2002 की अधिसूचना द्वारा पेंशन योजना का विकल्प चुना - अपीलकर्ता के दिवंगत पति ने दरभंगा, बिहार राज्य से पेंशन के लिए भुगतान का दावा किया - अपीलकर्ता के पति द्वारा पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी जहां 1,33,559 रुपये की वापसी की प्रार्थना की गई थी, जिसे गलत तरीके से रोक दिया गया था / अवैध रूप से उससे काट लिया गया था - उक्त रिट याचिका को 08.02.2013 को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार - उक्त रिट याचिका खारिज होने के बाद, अपीलकर्ता के पति ने उसी राहत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की - इसके बाद, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय से अपीलकर्ता के पति को दिनांक 07.10.2013 और 06.11.2013 के पत्र जारी किए गए - पत्र में कहा गया है कि चूंकि अपीलकर्ता के पति ने शुरू में 1998 की अधिसूचना के अनुसरण में पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था, वह वर्ष 2002 में पेंशन का विकल्प नहीं चुन सकता था - यह आगे कहा गया था कि क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा पेंशन का गलत तरीके से निपटान किया गया था, इसलिए, अपीलकर्ता के पति से 08 लाख रुपये से अधिक की वसूली की जानी थी - उन्हीं पत्रों के माध्यम से यह भी सूचित किया गया था

कि मासिक पेंशन का भुगतान 1-4-2002 से रोकने का निर्णय लिया गया था। नवंबर, 2013 - अपीलकर्ता के पति ने पटना उच्च न्यायालय में एक और रिट याचिका दायर की, जहां उन्होंने दिनांक 07.10.2013 और 06.11.2013 के पत्रों को चुनौती दी - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के पहले के आदेश दिनांक 08.02.2013 को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि रिट याचिका खारिज होने के बाद, याचिकाकर्ता ने एक और रिट दायर की थी याचिका झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष और यह लंबित था, ने माना कि पेंशन रोकने का आदेश सेवानिवृत्ति लाभ का हिस्सा है, और याचिकाकर्ता को झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करनी चाहिए थी - इसलिए, पत्रों को चुनौती देने वाली रिट याचिका को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर फिर से खारिज कर दिया गया था - एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर एलपीए को भी खारिज कर दिया गया था - अपील पर, आयोजित किया गया था: उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दायर रिट याचिकाओं में तथ्यों और दलीलों पर सही ढंग से विचार नहीं किया - पहले की रिट याचिका गलत तरीके से रोकी गई/अवैध रूप से हिरासत में ली गई राशि की वापसी के लिए दायर की गई थी और बाद में दिनांक 07.10.2013 के पत्रों को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर की गई थी और 06.11.2013 दायर किया गया था जब 08 साल के बाद पेंशन का भुगतान रोक दिया गया था और अपीलकर्ता के पति को 08 लाख रुपये से अधिक की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था - बाद में रिट याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण पूरी तरह से अलग था - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर पहले की रिट याचिका को खारिज करने के कारण बाद की रिट याचिका को खारिज करने में त्रुटि की - एक सेवानिवृत्त के लिए, जो दरभंगा में बस गया है और पेंशन प्राप्त कर रहा है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके लिए झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर करना आवश्यक था, जहां उसकी पिछली रिट याचिका लंबित थी - पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था क्योंकि अपीलकर्ता का पति दरभंगा में पिछले 8 वर्षों से लगातार पेंशन प्राप्त कर रहा था - उसी स्थान पर पेंशन के रुकने ने एक कारण दिया कार्रवाई का - इस प्रकार, उक्त रिट याचिका को पटना उच्च न्यायालय में पुनर्जीवित किया जाता है।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय

आयोजित: 1. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 2006 की रिट याचिका संख्या 13955 और 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 में तथ्यों और दलीलों पर सही ढंग से विचार नहीं किया। वर्ष 2006 में याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई पिछली रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने गलत तरीके से रोकी गई/अवैध रूप से हिरासत में ली गई 1,33,559/- रुपये की राशि वापस करने की प्रार्थना की थी। जब पहले रिट याचिका दायर की गई थी, तब पेंशन का भुगतान न करने या पेंशन रोकने का कोई मुद्दा नहीं था क्योंकि पेंशन मई, 2005 से शुरू की गई थी। 2014 की बाद की रिट याचिका संख्या 5999 तब दायर की गई थी जब 08 साल बाद पेंशन का भुगतान रोक दिया गया था और याचिकाकर्ता को 8,09,268 रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था। 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 दायर करने की कार्रवाई का कारण पूरी तरह से अलग था। एकल न्यायाधीश ने यह निर्णय देने में त्रुटि की कि क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर पूर्व रिट याचिका को खारिज करने के मद्देनजर, रिट याचिका भी खारिज की जाती है। [अनुच्छेद 15] [290-डी-जी]

2. एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया दूसरा कारण यह है कि याचिकाकर्ता को झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करनी चाहिए थी, यह भी इस न्यायालय की सिफारिश नहीं करता है। दरभंगा में बसे और जिला दरभंगा में पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके लिए झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर करना आवश्यक था, जहां उसकी पिछली रिट याचिका लंबित थी। पहले की रिट याचिका की विषय वस्तु पूरी तरह से अलग थी और रिट याचिका की बर्खास्तगी याचिकाकर्ता को उसी उच्च न्यायालय में बाद में रिट याचिका दायर करने से नहीं रोकती है। [अनुच्छेद 16] [290-जीएच; 291-ए]

3. वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, इस न्यायालय का विचार है कि कार्रवाई के कारण का हिस्सा पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है। मृतक याचिकाकर्ता भारतीय स्टेट बैंक, दरभंगा में अपने बचत बैंक खाते में पिछले 08 वर्षों से लगातार पेंशन प्राप्त कर रहा था। अपीलकर्ता के दिवंगत पति की पेंशन के रोके जाने से वह अपने मूल स्थान पर प्रभावित हुआ, वह पेंशन के लाभ से वंचित हो गया जो उसे अपने नियोक्ता से मिल रहा था। नियोक्ता को एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को उस स्थान को इंगित करने की आवश्यकता होती है जहां वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त करेगा।

अपीलकर्ता के दिवंगत पति ने भारतीय स्टेट बैंक, दरभबगा, बिहार राज्य में अपनी पे प्राप्त करने का विकल्प चुना था, जो उसका मूल स्थान था, जहां से वह पिछले 08 वर्षों से नियमित रूप से अपनी पेंशन ले रहा था, पेंशन के रुकने से कार्रवाई का कारण बना, जो उस स्थान पर उत्पन्न हुआ जहां याचिकाकर्ता लगातार पेंशन प्राप्त कर रहा था। इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार है कि एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ का यह दृष्टिकोण कि रिट याचिका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर सुनवाई योग्य नहीं है, पूरी तरह से गलत था और इससे याचिकाकर्ता को बहुत कठिनाई हुई है। इसलिए, पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को पुनर्जीवित किया जाता है। [अनुच्छेद 29] [298-एफएच; 299-ए-बी]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बनाम उत्पल कुमार बसु और अन्य। **(1994) 4 एससीसी 711: [1994] 1 पूरक. एससीआर 252;** *नवीनचंद्र एन. मजीठिया बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य* **(2000) 7 एससीसी 640: [2000] 3 पूरक (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और (2004) 3 एससीसी 277: [2004] 2 एससीआर 202;** *कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड वी। भारत संघ और एन.आर.* **(2004) 6 एससीसी 254: [2004] 1 पूरक एससीआर 841;** *नवल किशोर शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य***। (2014) 9 एससीसी 329: [2014] 7 एससीआर 1027 - पर भरोसा किया।**

सरयू सिंह वि. भारत संघ और अन्य। **2015 (2) पीएलजेआर 256 -संदर्भित।**

केस लॉ संदर्भ

[1994] 1 पूरक एससीआर	**252 पर निर्भर**	**अनुच्छेद 21**
[2000] 3 पूरक एससीआर	**82 पर भरोसा**	**अनुच्छेद 22**
[2004] 2 एससीआर	**202 पर भरोसा**	**अनुच्छेद 24**
[2004] 1 सप्ल। एससीआर	**841 पर निर्भर**	**अनुच्छेद 25**
[2014] 7 एससीआर	**1027 पर निर्भर**	**अनुच्छेद 26**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार है: सिविल अपील संख्या 3630/2020

2017 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1265 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 03.05.2018 से।

अरविंद कुमार गुप्ता, ऋषि भारद्वाज, शौर्य डोगरा, अभिसूमत गुप्ता, जयंत के. सूद, एडवोकेट जीएस मक्कड़, श्रीकुमार सी.एन., भुवन कपूर, उद्यम मुखर्जी, कृष्णयन सेन, ललित कुमार, कौस्तुभ शुक्ला, पारिजात किशोर, अभय सिंह, अधिवक्ता उपस्थित होने वाले पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय

अशोक भूषण, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील 2017 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1265 में पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले पर सवाल उठाते हुए दायर की गई है, जिसमें अपीलकर्ता की लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया गया था। लेटर्स पेटेंट अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 04.08.2017 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसके द्वारा उनके दिवंगत पति द्वारा दायर 2014 की रिट याचिका संख्या 5999, जिसमें उन्हें उनके पति की मृत्यु के बाद प्रतिस्थापित किया गया था, को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

3. इस अपील पर निर्णय लेने के लिए मामले के संक्षिप्त तथ्य हैं:

3.1 अपीलकर्ता श्री वशिष्ठ नारायण मिश्रा के पति भारतीय कोल लिमिटेड में कार्यरत थे। वह मोइरा कोलियरी, बांकोला क्षेत्र, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में कार्यरत थे। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने कोयला खान भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 3ङ के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के अधिक्रमण में परिवार कोयला खान पेंशन योजना, 1998 दिनांक 05031998 अधिसूचित की है। अपीलकर्ता के दिवंगत पति ने दिनांक 05.03.1998 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना।

3.2 दिनांक 09.01.2002 की अधिसूचना द्वारा कोयला खान पेंशन योजना, 1998 में संशोधन करते हुए योजना में अनुच्छेद 2क अंतस्थापित किया गया था जिसमें यह प्रावधान

किया गया था कि कोई कर्मचारी, जिसने कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 का विकल्प नहीं दिया था लेकिन भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आता है, नौ माह की अवधि के भीतर पेंशन का विकल्प चुन सकता है। दिनांक 09012002 की अधिसूचना के बाद ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि द्वारा इसे सभी क्षेत्रीय आयुक्तों/सहायक आयुक्तों को परिचालित किया गया था।

3.3 अपीलकर्ता के पति ने दिनांक 09.01.2002 की अधिसूचना के अनुसरण में पेंशन योजना का विकल्प प्रस्तुत किया, जिसे शांति देवी उर्फ शांति मिश्रा बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा प्रबंधक, मोइरा कोलियरी द्वारा वरिष्ठ कार्मिक अधिकारियों को भेजा गया पत्र दिनांक 18.11.2003 जिसमें बीएन मिश्रा के भविष्य निधि खाते से 1,38,164 रुपये उनके पेंशन फंड में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। क्षेत्रीय आयुक्त के दिनांक 20.11.2003 के अगले पत्र द्वारा यह सूचित किया गया था कि योजना, 1998 के अनुच्छेद 4 (2) के तहत 48,467 रुपये की राशि समायोजित की गई है। स्वर्गीय बीएन मिश्रा 30.04.2005 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। पेंशन के निपटान के लिए उनके कागजात क्षेत्रीय आयुक्त-1, कोयला खान भविष्य निधि, आसनसोल को भेज दिए गए थे। क्षेत्रीय आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र-1, आसनसोल द्वारा लिखे गए दिनांक 30.11.2005 के पत्र द्वारा अपीलकर्ता के दिवंगत पति को पेंशन अंशदान की वसूली के लिए 39,198/- रुपये की राशि जमा करने के लिए कहा गया था। श्री मिश्रा को सेवानिवृत्ति से लगभग 14 महीने बाद पेंशन मंजूर की गई थी, इसके बाद, उन्हें मई, 2005 से पेंशन मिलनी शुरू हो गई।

3.4 स्वर्गीय श्री बीएन मिश्रा ग्राम भुस्कोल, पुलिस स्टेशन, दरभंगा, जिला दरभंगा के मूल निवासी होने के कारण उन्होंने दरभंगा, बिहार राज्य से पेंशन के भुगतान का दावा किया था। भारतीय स्टेट बैंक, दरभंगा, बिहार राज्य में स्वर्गीय श्री बीएन मिश्रा के खाते में पेंशन शुरू की गई। स्वर्गीय श्री बीएन मिश्रा द्वारा पटना उच्च न्यायालय में 2006 की एक रिट याचिका संख्या 13955 दायर की गई थी, जहां उन्होंने 1,33,559 रुपये की वापसी के लिए प्रार्थना की थी, जिसे गलत तरीके से रोका गया था / अवैध रूप से रिट याचिकाकर्ता से काट लिया गया था। उक्त रिट याचिका को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर 08.02.2013 को खारिज कर दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल राज्य में उन प्राधिकरणों और संगठनों के तहत सेवा की जो

या तो पश्चिम बंगाल या झारखंड राज्यों में स्थित हैं, इसलिए, पटना उच्च न्यायालय का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था।

3.5 दिनांक 08.02.2013 को 2006 की उपर्युक्त रिट याचिका संख्या 13955 के खारिज होने के बाद स्वर्गीय श्री बी. एन. मिश्रा ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष 2006 की रिट याचिका संख्या 13955 में दावा की गई राहत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में 2013 की रिट याचिका संख्या 4930 दायर की। जब झारखंड उच्च न्यायालय में स्वर्गीय श्री बीएन मिश्रा द्वारा दायर रिट याचिका का सूचना क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आसनसोल के कार्यालय द्वारा प्राप्त किया गया था, तो अपीलकर्ता के पति को उनके निवास स्थान, अर्थात ग्राम भुस्कोल, पुलिस स्टेशन दरभंगा में दिनांक 07.10.2013 का एक पत्र जारी किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में दिनांक 10-11-2008 के अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि श्री बीएन मिश्रा ने 1998 की अधिसूचना के अनुसरण में प्रारंभ में पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था, इसलिए वह वर्ष 2002 में पेंशन का विकल्प नहीं चुन सकते थे। यह कहा गया था कि श्री बीएन मिश्रा की पेंशन क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा गलती से तय की गई थी, इसलिए मई, 2005 से सितंबर, 2013 तक पेंशन भुगतान के लिए 8,01,334/- रुपये वसूल किए जाने हैं।

3.6 क्षेत्रीय आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र-1, आसनसोल द्वारा जारी दिनांक 06.11.2013 के अगले पत्र द्वारा उन्हें 8,09,268/- रुपये की राशि और ब्याज सहित संपूर्ण पेंशन अंशदान वापस करने का निदेश दिया गया था। उन् हें सूचित किया गया कि नवम् बर, 2013 से मासिक पेंशन का भुगतान रोकने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 07.10.2013 का पत्र प्राप्त होने के बाद श्री बी.एन.मिश्रा ने दिनांक 07.11.2013 को उत्तर भेजा जिसमें कहा गया था कि दिनांक 07.10.2013 का पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री बीएन मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर क्षेत्रीय आयुक्त, क्षेत्र-1, आसनसोल के विरुद्ध उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई के कारण व्यक्तिगत पक्षपात के कारण जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने सचिव, कोयला मंत्रालय और आयोग को अभ्यावेदन भेजे।

3.7 पटना उच्च न्यायालय में स्वर्गीय श्री बीएन मिश्रा द्वारा 2014 की एक रिट याचिका संख्या 5999 दायर की गई थी, जहां उन्होंने दिनांक 07.10.2013 और

06.11.2013 के पत्र को चुनौती दी थी और याचिकाकर्ता को ब्याज के साथ पेंशन का भुगतान करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की थी। रिट याचिका 04.08.2017 को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आई। विद्वान एकल न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के दिनांक 08.02.2013 के पहले के आदेश पर ध्यान दिया जिसके द्वारा 2006 की उनकी पूर्व रिट याचिका संख्या 13955 को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि इसी तरह के तथ्यों के आधार पर, उक्त रिट याचिका को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर 08.02.2013 को खारिज कर दिया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी। जो लंबित है, पेंशन रोकने का आदेश सेवानिवृत्ति लाभ का हिस्सा है, इसलिए, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर रिट याचिका खारिज कर दी गई है। विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 04.08.2017 के फैसले के खिलाफ 2017 का एलपीए संख्या 1265 दायर किया गया था। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, श्री बीएन मिश्रा की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी शांति देवी को रिट याचिकाकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। एलपीए विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध खंडपीठ के समक्ष दायर किया गया था, जिसे आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है, किस आदेश से व्यथित होकर यह अपील दायर की गई है।

4. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री अरविंद कुमार गुप्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए श्री श्रीकुमार सी.एन. और प्रतिवादी संख्या 5 और 8 के लिए श्री कौस्तुभ शुक्ला को सुना है। श्री उद्यम मुखर्जी प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित हुए।

5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने में त्रुटि की है। पटना उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र था। कार्रवाई के कारण का हिस्सा पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ था। स्वर्गीय श्री बीएन मिश्रा 01-04-2008 से भारतीय स्टेट बैंक, दरभंगा से पेंशन प्राप्त कर रहे थे। 30-04-2005 को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मई, 2005 में उनकी सेवानिवृत्ति हुई। दिनांक 07102013 और 06112013 को आदेश जारी होने के बाद दिनांक 0710334/- और 809,268/- रुपए की राशि वापस करने और 01042013 से पेंशन रोकने का निदेश दिया

गया है। नवम्बर, 2013 में दरभंगा में कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ जहां स्वर्गीय श्री बीएन मिश्रा रह रहे थे और पेंशन प्राप्त कर रहे थे। 2006 की पिछली रिट याचिका संख्या 13955 कार्रवाई के विभिन्न कारणों पर दायर की गई थी, जहां अवैध रूप से काटी गई राशि की वापसी के लिए पर्याप्त प्रार्थना की गई थी, जबकि 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 कार्रवाई के पूरी तरह से अलग कारण पर थी। स्वर्गीय श्री बीएन मिश्रा दरभंगा में पेंशन प्राप्त कर रहे थे, जिसे पेंशन नवंबर, 2013 से रोक दी गई थी। कार्रवाई का कारण पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ और विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ ने पहले की रिट याचिका को खारिज करने पर भरोसा करते हुए रिट याचिका को खारिज करने में गलती की, जबकि दोनों रिट याचिकाओं की कार्रवाई का कारण अलग-अलग था और 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 को क्षेत्रीय न्यायशास्त्र की कमी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था।

6. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिका को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। वह प्रस्तुत करता है कि रिट याचिका खारिज होने के बाद स्वर्गीय श्री बीएन मिश्रा ने झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी, जो रिट याचिका तब भी लंबित थी जब उन्होंने 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 दायर की थी और रिट याचिका पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता था। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान वकील इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि कार्रवाई के कारण का हिस्सा पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था, हालांकि, वह प्रस्तुत करता है कि ***अदालत संयोजक*** के सिद्धांत पर, रिट याचिका पर पटना में विचार नहीं किया जा सकता था और रिट याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना चाहिए था।

7. प्रतिवादी संख्या 5 और 8 के विद्वान वकील, श्री कौस्तुभ शुक्ला प्रस्तुत करते हैं कि स्वर्गीय श्री बीएन मिश्रा ने पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड में सेवा की थी और बर्दवान, पश्चिम बंगाल से 30.04.2005 को सेवानिवृत्त हुए थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि श्री बीएन मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने के बाद पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर नहीं कर सकते थे। अपीलकर्ता के पति ने 1998 में कोयला खान पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था, लेकिन उसने बाद में

अधिसूचना दिनांक 09.01.2002 के बाद वर्ष 2002 में दूसरी बार योजना का विकल्प चुना। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा की गई कटौतियां कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अनुसार थीं। इससे पहले याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका 2006 की रिट याचिका संख्या 13955 थी, जिसे पटना उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज कर दिया था और श्री बीएन मिश्रा द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी, उक्त निर्णय अंतिम हो गया था। मिश्रा ने अपनी पिछली रिट याचिका को खारिज करने के बाद रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष 2013 की रिट याचिका संख्या 4930 दायर की, जो स्पष्ट रूप से साबित करती है कि श्री बीएन मिश्रा ने झारखंड उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया था और वहां अपनी रिट याचिका का पीछा किया था। केवल तथ्य यह है कि दरभंगा में दिनांक 07.10.2013 और 06.11.2013 के पत्र प्राप्त हुए थे, पटना उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

8. प्रतिवादी नंबर 4 के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने भी उपरोक्त प्रस्तुतियों को अपनाया।

9. पक्षकारों के विद्वान वकीलों ने भी इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के साथ-साथ पटना उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है, जिन पर विस्तार से विचार करते समय ध्यान दिया जाएगा।

10. पक्षकारों के विद्वान वकीलों की प्रस्तुतियों और अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से, इस अपील में निम्नलिखित प्रश्न उठे हैं: -

(i) क्या स्वर्गीय श्री बीएन मिश्रा द्वारा दायर रिट याचिका 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 होने के कारण 2006 की रिट याचिका संख्या 13955 के समान है और पटना उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र था?

(ii) क्या 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 दायर करने के लिए कार्रवाई का हिस्सा पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ?

11. दोनों प्रश्नों का परस्पर संबंध होने के कारण एक साथ लिया जा रहा है। हम सबसे पहले 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 में प्रासंगिक दलीलों पर ध्यान दे सकते हैं,

जो रिट याचिका में राहत का दावा करने के लिए भौतिक तथ्य या अभिन्न तथ्य हैं। रिट याचिका के अनुच्छेदग्राफ 5 में, याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि वह 30.04.2005 को सेवानिवृत्त हुआ और उसके बाद दरभंगा जिला, बिहार राज्य में अपने मूल स्थान पर बस गया, जहां अनुच्छेदग्राफ 20 और 22 में, याचिकाकर्ता ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्र-1, आसनसोल द्वारा जारी दिनांक 07.10.2013 के पत्र और दिनांक 06.11.2013 के पत्र के बारे में दलील दी है। अनुच्छेदग्राफ 5, 20 और 22 तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं: -

"**5**. याचिकाकर्ता को बाद में मोइरा कोलियरी, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, बैंकोला एरिया, पी ओ मोइरा, जिला - बर्दवान में कार्मिक प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया, जहां से वह 30/04/2005 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद दरभंगा जिला, बिहार में अपने पैतृक गांव में बस गए, जहां भारतीय स्टेट बैंक, दरभंगा के साथ उसके बचत खाते में उसकी मासिक पेंशन का भुगतान मई, 2005 से किया जा रहा है।

सेवानिवृत्त की सूचना पत्र संख्या ई सी एल/सी-5 (डी) अधिवर्षिता/ई ई 1572 दिनांक 23/24/11/2004 इसके साथ संलग्न है और अनुलग्नक -1 के रूप में चिह्नित है।

20. कि विद्वान केंद्र सरकार के वकील से रिट याचिका की एक प्रति प्राप्त होने पर क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त, क्षेत्र 1, आसनसोल ने दिनांक 10-10-2010 के माध्यम से एक सूचना जारी किया। सीपीएफ/32/कानूनी/बीएन मिश्रा/आर-1/एएसएन/3481 दिनांक 7/10/2013 जिसमें उन्होंने कोयला खान पेंशन योजना 1998 के अनुच्छेद -15 के प्रावधानों के खिलाफ याचिकाकर्ता को मई 2005 से अब तक पेंशन का भुगतान पूरी तरह से ए बी सी डी ई एफ जी एच 289 के रूप में घोषित किया, जिसमें कहा गया है कि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा और चूंकि याचिकाकर्ता ने पहले नकारात्मक विकल्प प्रस्तुत किया था, इसलिए बाद में सकारात्मक में विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा योजना के खिलाफ है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को मई 2005 से अक्टूबर 2013 तक भुगतान किए गए ब्याज के साथ 8,01,334 रुपये की पेंशन की पूरी राशि वापस करने का भी निर्देश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगी को उपर्युक्त सूचना के माध्यम से यह भी सूचित किया गया था कि उसे पेंशन का भुगतान नवम्बर, 2013 से रोक दिया जाएगा।

पत्र सं. सीपीएफ/32/कानूनी/बीएन मिश्रा/आर-1/एएसएन/3481 दिनांक 7/10/2013 के साथ-साथ सीएमपीएस 1998 के अनुच्छेद 15 के प्रासंगिक भाग को इसके साथ संलग्न किया गया है और अनुलग्नक-12 के रूप में चिह्नित किया गया है।

22. कि क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त ने याचिकाकर्ता द्वारा जारी सूचना के जवाब की प्रतीक्षा नहीं की और इसके बजाय जल्दबाजी में पत्र संख्या 2010 जारी किया। मिश्रा/आर-1/4056 दिनांक 6/11/2013 के आदेश के तहत उन्होंने याचिकाकर्ता को नवंबर 2013 से पेंशन का भुगतान बंद कर दिया और उसे मई 2005 से अक्टूबर 2013 तक याचिकाकर्ता को भुगतान की गई पेंशन की पूरी राशि 8,09,268 रुपये वापस करने का भी निर्देश दिया। पत्र सं. सीपीएफ/32/1/कानूनी/बीएन मिश्रा/आर-1/4056 दिनांक 6/11/2013 इसके साथ संलग्न है और अनुलग्नक22. कि क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त ने याचिकाकर्ता द्वारा जारी सूचना के जवाब की प्रतीक्षा नहीं की और इसके बजाय जल्दबाजी में पत्र संख्या 2010 जारी किया। मिश्रा/आर-1/4056 दिनांक 6/11/2013 के आदेश के तहत उन्होंने याचिकाकर्ता को नवंबर 2013 से पेंशन का भुगतान बंद कर दिया और उसे मई 2005 से अक्टूबर 2013 तक याचिकाकर्ता को भुगतान की गई पेंशन की पूरी राशि 8,09,268 रुपये वापस करने का भी निर्देश दिया।

पत्र सं. सीपीएफ/32/1/कानूनी/बीएन मिश्रा/आर-1/4056 दिनांक 6/11/2013 इसके साथ संलग्न है और अनुलग्नक-14 के रूप में चिह्नित है।-14 के रूप में चिह्नित है।

15. विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2006 की रिट याचिका संख्या 13955 और 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 में तथ्यों और दलीलों पर सही ढंग से विचार नहीं किया। याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2006 में दायर की गई पिछली रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने गलत तरीके से रोकी गई/अवैध रूप से हिरासत में ली गई 1,33,559/- रुपये की राशि वापस करने की प्रार्थना की थी। जब पहले रिट याचिका दायर की गई थी, तब पेंशन का भुगतान न करने या पेंशन रोकने का कोई मुद्दा नहीं था क्योंकि पेंशन मई, 2005 से शुरू की गई थी। 2014 की बाद की रिट याचिका संख्या 5999 तब दायर की गई थी जब 08 साल बाद पेंशन का भुगतान रोक दिया गया था और याचिकाकर्ता को 8,09,268 रुपये की राशि वापस करने

का निर्देश दिया गया था। 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 दायर करने की कार्रवाई का कारण पूरी तरह से अलग था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह निर्णय देने में त्रुटि की कि क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर पूर्व रिट याचिका को खारिज किए जाने के मद्देनजर, रिट याचिका भी खारिज की जाती है।

16. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया दूसरा कारण यह है कि याचिकाकर्ता को झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करनी चाहिए थी, यह भी हमारी सराहना नहीं करता है। दरभंगा में बसे और जिला दरभंगा में पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके लिए झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर करना आवश्यक था, जहां उसकी पिछली रिट याचिका लंबित थी। पहले की रिट याचिका की विषय वस्तु पूरी तरह से अलग थी और रिट याचिका की बर्खास्तगी याचिकाकर्ता को उसी उच्च न्यायालय में बाद में रिट याचिका दायर करने से नहीं रोकती है।

17. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट याचिका के तथ्यों या दलीलों का विज्ञापन नहीं किया और केवल विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के अनुच्छेदग्राफ 4 और 5 को उद्धृत करने के बाद ही रिट याचिकाकर्ता द्वारा एल पी ए में उठाए गए किसी भी मुद्दे पर विज्ञापन दिए बिना रिट याचिका को खारिज कर दिया। 2017 के एलपीए संख्या 1265 के आधार की प्रति अनुलग्नक पी -24 के रूप में दायर की गई है, जो इंगित करती है कि याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से प्रासंगिक तथ्यों की वकालत की है और विशेष रूप से कहा है कि वर्ष 2013 में उत्पन्न कार्रवाई का कारण 08 साल पहले वर्ष 2006 में दायर रिट याचिका का विषय नहीं हो सकता है। रिट याचिका में मुख्य दलीलों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था और उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया था, हमें यह विज्ञापित करने की आवश्यकता है कि क्या रिट याचिका पर विचार करने के लिए **कार्रवाई का कोई कारण** था।

18. सिविल प्रक्रिया संहिता पर मुल्ला ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 पर टिप्पणी करते हुए निम्नलिखित शब्दों में कार्रवाई के कारण को परिभाषित किया: -

"अभिव्यक्ति 'कार्रवाई का कारण' ने न्यायिक रूप से स्थापित अर्थ प्राप्त कर लिया है। प्रतिबंधित अर्थ में 'कार्रवाई का कारण' का अर्थ है कार्रवाई के लिए अधिकार या तत्काल अवसर का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियां। व्यापक अर्थों में, इसका अर्थ है सूट के रखरखाव के लिए आवश्यक शर्तें, जिसमें न केवल अधिकार का उल्लंघन शामिल है, बल्कि उल्लंघन स्वयं अधिकार के साथ युग्मित है। स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति का अर्थ है हर तथ्य जिसके द्वारा वादी के लिए यह साबित करना आवश्यक होगा, यदि ट्रेवर्स किया जाता है, तो न्यायालय के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए............"

19. पी. रामनाथ अय्यर ने एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, तीसरा संस्करण, खंड 1 में कार्रवाई के कारण को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है: -

"'कार्रवाई के कारण' को केवल एक तथ्यात्मक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका अस्तित्व एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय से उपाय प्राप्त करने का अधिकार देता है। वाक्यांश को शुरुआती समय से ही हर तथ्य को शामिल करने के लिए आयोजित किया गया है जो वादी को सफल होने का हकदार साबित करने के लिए सामग्री है, और हर तथ्य जिसे एक प्रतिवादी को पार करने का अधिकार होगा। "कार्रवाई का कारण" का अर्थ प्रतिवादी की ओर से उस विशेष कार्य से भी लिया गया है जो वादी को उसकी शिकायत का कारण देता है, या शिकायत की विषय वस्तु कार्रवाई की स्थापना करती है, न कि केवल कार्रवाई का तकनीकी कारण।

20. ब्लैक लॉ डिक्शनरी निम्नलिखित शब्दों में कार्रवाई के कारण को परिभाषित करता है: -

"मुकदमा करने के लिए एक या अधिक आधारों को जन्म देने वाले ऑपरेटिव तथ्यों का एक समूह; एक तथ्यात्मक स्थिति जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अदालत में उपाय प्राप्त करने का अधिकार देती है..........."

21. इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 266 के संदर्भ में कार्रवाई के कारण पर विचार करने का अवसर मिला था और उसने बड़ी संख्या में मामलों में "**कार्रवाई का कारण**"

अभिव्यक्ति की व्याख्या की थी। हम तेल और **प्राकृतिक गैस आयोग बनाम उत्पल कुमार बसु और अन्य, (1994) 4 एससीसी 711** में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जहां अनुच्छेदग्राफ 5 और 6 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:

> "5. अनुच्छेद 226 का खंड (1) एक गैर-आज्ञाकारी खंड से शुरू होता है - अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी - और यह उपबंध करता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को "उन सभी क्षेत्रों में, जिनके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है", किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, जिसके अंतर्गत उपयुक्त मामलों में, कोई सरकार, "उन प्रदेशों के भीतर" भाग III द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए निदेश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 226 के खंड (2) के अधीन उच्च न्यायालय खंड (1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा यदि कार्रवाई का कारण, पूर्णतः या भागत, उस राज्यक्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ था जिस पर वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसी सरकार या प्राधिकारी का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास उन राज्यक्षेत्रों के भीतर नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 226 के उपर्युक्त दो खंडों को पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई उच्च न्यायालय संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, यदि कार्रवाई का कारण, पूर्ण या आंशिक रूप से, उन क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न हुआ था जिनके संबंध में यह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, इस बात के बावजूद कि सरकार या प्राधिकरण की सीट या उस व्यक्ति का निवास जिसके खिलाफ निर्देश, आदेश या रिट जारी की गई है, उक्त क्षेत्रों के भीतर नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए, एनआईसीसीओ को यह दिखाना होगा कि कार्रवाई के कारण का कम से कम एक हिस्सा उस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ था। रिट याचिका में इसका मामला अधिक से अधिक है।

6. यह अच्छी तरह से तय है कि अभिव्यक्ति "कार्रवाई का कारण" का अर्थ तथ्यों का वह बंडल है जिसे याचिकाकर्ता को साबित करना होगा, यदि उसे अदालत द्वारा उसके पक्ष में निर्णय देने का हकदार होना चाहिए। चांद कौर बनाम प्रताप सिंह [आईएलआर (1889) 16 कैल 98, 102: 15 आईए 156] में लॉर्ड वाटसन ने कहा:

> "... कार्रवाई के कारण का प्रतिवादी द्वारा स्थापित किए जा सकने वाले बचाव से कोई संबंध नहीं है, न ही यह वादी द्वारा प्रार्थना की गई राहत के चरित्र पर निर्भर करता है। यह पूरी तरह से कार्रवाई के कारण के रूप में वाद में निर्धारित आधार को संदर्भित करता है, या, दूसरे शब्दों में, मीडिया के लिए जिस पर वादी अदालत को अपने पक्ष में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहता है।"

इसलिए, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी की आपत्ति का निर्धारण करने में, अदालत को कार्रवाई के कारण के समर्थन में दिए गए सभी तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, हालांकि उक्त तथ्यों की शुद्धता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू किए बिना। दूसरे शब्दों में, इस प्रश्न का उत्तर कि क्या उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है, याचिका में किए गए कथनों के आधार पर उत्तर दिया जाना चाहिए, सच्चाई या अन्यथा सारहीन होने के कारण। दूसरे शब्दों में कहें तो याचिका में दिए गए तथ्यों के आधार पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के सवाल पर फैसला किया जाना चाहिए. इसलिए, यह प्रश्न कि क्या वर्तमान मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास कथित तथ्यों पर भी विचाराधीन रिट याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था, इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि क्या अनुच्छेदग्राफ 5, 7, 18, 22, 26 और 43 में किए गए कथन कानून में यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ था।

22. **नवीनचंद्र एन. मजीठिया बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2000) 7 एससीसी 640** में इस न्यायालय को अनुच्छेद 226 (2) के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर विचार करने का अवसर मिला था। अनुच्छेद 226 (2) में किए गए संवैधानिक संशोधन से निपटते हुए, इस न्यायालय ने अनुच्छेदग्राफ 37 में निम्नलिखित निर्धारित किया: -

"37. अनुच्छेद में खंड (2) को अंतःस्थापित करके संशोधन का उद्देश्य *चुनाव आयोग बनाम साका वेंकट सुब्बा राव [एआईआर 1953 एससी 210*] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करना और ऊपर उद्धृत निर्णयों में उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित दृष्टिकोण को बहाल करना था। इस प्रकार उच्च न्यायालयों का प्रयोग किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है जिनके भीतर "कार्रवाई का कारण, पूर्ण या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है" और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संबंधित प्राधिकरण की सीट उस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा से बाहर है। इस प्रकार संशोधन का उद्देश्य विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा जारी रिटों तक पहुंचने के लिए क्षेत्र की चौड़ाई को चौड़ा करना है।

23. यह आगे आयोजित किया गया था कि "कार्रवाई का कारण, पूर्ण या आंशिक रूप से, उत्पन्न होता है" शब्दों का संयोजन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 से उठाया गया प्रतीत होता है। इस न्यायालय ने अनुच्छेदग्राफ 39 में रीड बनाम ब्राउन में लॉर्ड ईशर द्वारा दी गई "कार्रवाई के कारण" की परिभाषा को भी उद्धृत किया। अनुच्छेदग्राफ 38, 39 और 41 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया था: -

"38. "कार्रवाई का कारण" एक ऐसी घटना है जिसे कानूनी भाषा में अच्छी तरह से समझा जाता है। महापात्र, जे ने प्रसिद्ध शब्दकोशों का उल्लेख करते हुए उक्त अभिव्यक्ति के आयात को अच्छी तरह से चित्रित किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि "कार्रवाई का कारण, पूर्ण या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है" शब्दों का संयोजन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 से उठाया गया है, जो धारा अदालतों के क्षेत्राधिकार संबंधी पहलू से भी संबंधित है। उस धारा के अनुसार, मुकदमा उस अदालत में स्थापित किया जा सकता है जिसकी कानूनी सीमा के भीतर "कार्रवाई का कारण पूरी तरह से या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है"। न्यायिक घोषणाओं ने संविधान के पंद्रहवें संशोधन से पहले भी उक्त व्यापक अभिव्यक्ति की लगभग एक समान व्याख्या की है, जिसका अर्थ है "तथ्यों का बंडल जो वादी के लिए साबित करने के लिए आवश्यक होगा, यदि अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए"।

39. *रीड बनाम ब्राउन* [(1888) 22 क्यू बी डी 128: 58 अल जे बी क्यू 120: 60 ऐल टी 250 (सी ऐ)] लॉर्ड एशर, एम आर ने "कार्रवाई का कारण" वाक्यांश की परिभाषा को अपनाया कि इसका अर्थ है

"हर तथ्य जो वादी के लिए साबित करना आवश्यक होगा, यदि ट्रैवर्स किया जाता है, तो अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए। इसमें हर सबूत शामिल नहीं है जो प्रत्येक तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक है, लेकिन हर तथ्य जिसे साबित किया जाना आवश्यक है।

41. संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के संदर्भ में भी इस न्यायालय ने *राजस्थान बनाम स्वाइका प्रॉपर्टीज* [(1985) 3 एससीसी 217] के तहत अभिव्यक्ति "कार्रवाई का कारण, पूर्ण या आंशिक रूप से, उत्पन्न होता है" के लिए एक ही व्याख्या को अपनाया। *तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बनाम उत्पल कुमार बसु* [(1994) 4 एससीसी 711] में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय है कि अभिव्यक्ति "कार्रवाई का कारण" का अर्थ तथ्यों का वह बंडल है जिसे याचिकाकर्ता को साबित करना होगा, अगर उसे अपने पक्ष में निर्णय देने का हकदार होना चाहिए। अहमदी की अभिव्यक्ति की इतनी व्यापक व्याख्या करने के बाद, जे. (जैसा कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश तब थे) एमएन वेंकटचलैया, सीजे और बीपी जीवन रेड्डी, जे के लिए बोलते हुए, उच्च न्यायालयों को अन्य उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ चेतावनी देने के लिए इस अवसर का उपयोग किया, केवल उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर होने वाली कार्रवाई के कारण से जुड़ी कुछ महत्वहीन घटना के आधार पर, जिसके लिए वादी पहुंचता है अपनी पसंद या सुविधा पर। निम्नलिखित ऐसे अवलोकन हैं। (एससीसी पृष्ठ 722, अनुच्छेद 12)

"यदि कोई धारणा बनती है कि अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में भी, अदालत के कुछ सदस्य इस दलील पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए तैयार होंगे कि कुछ घटना, हालांकि तुच्छ और कार्रवाई के कारण से असंबद्ध थी, उक्त अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर हुई थी, तो वादी ऐसे सदस्यों के समक्ष कारण लेकर प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे, जिससे बचने योग्य संदेह पैदा होगा। इससे संस्था की गरिमा कम होगी और पूरी व्यवस्था उपहास में डूब जाएगी। हमें यह कहते हुए बहुत दुख हो

रहा है परंतु यदि हम बढ़ती हुई प्रवृत्ति की दृढ़ता से निंदा नहीं करेंगे तो हमें डर है कि हम संस्था और न्याय प्रशासन प्रणाली के प्रति अपने कर्तव्य में असफल होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमें ऐसी स्थिति से निपटने का दूसरा अवसर नहीं मिलेगा।

24. *कुंजन नायर शिवरामन नायर बनाम नारायणन नायर और अन्य, (2004) 3 एससीसी 277* में, इस न्यायालय ने अभिव्यक्ति "कार्रवाई का कारण" की व्याख्या की और अनुमोदन के साथ कार्रवाई के कारण को उद्धृत किया है जैसा कि अनुच्छेदग्राफ 16 और 17 में इंग्लैंड के हाल्सबरी के कानूनों द्वारा परिभाषित किया गया है: -

"**16**. अभिव्यक्ति "कार्रवाई का कारण" ने न्यायिक रूप से तय अर्थ प्राप्त कर लिया है। प्रतिबंधित अर्थ में, कार्रवाई के कारण का अर्थ है कार्रवाई के लिए अधिकार या तत्काल अवसर का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियां। व्यापक अर्थों में, इसका अर्थ है वाद के रखरखाव के लिए आवश्यक शर्तें, जिसमें न केवल अधिकार का उल्लंघन शामिल है, बल्कि शांति देवी उर्फ शांति मिश्रा बनाम भारत संघ और अन्य के साथ युग्मित उल्लंघन भी शामिल है। अधिकार ही स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति का अर्थ है हर तथ्य जो वादी के लिए साबित करने के लिए आवश्यक होगा, यदि ट्रैवर्स किया जाता है, तो अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए। प्रत्येक तथ्य जिसे साबित करना आवश्यक है, जैसा कि प्रत्येक तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य के हर टुकड़े से अलग है, "कार्रवाई के कारण" में शामिल है।

17*. इंग्लैंड के हाल्सबरी के कानून (4 वें संस्करण)* में यह निम्नानुसार कहा गया है:

> "'कार्रवाई का कारण' को केवल एक तथ्यात्मक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका अस्तित्व एक व्यक्ति को अदालत से दूसरे व्यक्ति के खिलाफ एक उपाय प्राप्त करने का अधिकार देता है। वाक्यांश को शुरुआती समय से ही हर तथ्य को शामिल करने के लिए आयोजित किया गया है जो वादी को सफल होने का हकदार साबित करने के लिए सामग्री है, और हर तथ्य जिसे एक प्रतिवादी को पार करने का अधिकार होगा। 'कार्रवाई का कारण' का अर्थ प्रतिवादी की ओर से उस विशेष कार्य से भी लिया गया है जो वादी को

शिकायत का कारण देता है, या कार्रवाई की स्थापना करने वाली शिकायत का विषय-वस्तु, न कि केवल कार्रवाई का तकनीकी कारण।"

25. एक अन्य निर्णय जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है **कुसुम सिल्ली एवं मिश्र धातु लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, (2004) 6 एससीसी 254** जिसमें इस न्यायालय ने अनुच्छेद 6 में कार्रवाई के कारण का अर्थ दोहराया। इस न्यायालय ने दोहराया कि भले ही कार्रवाई के कारण का एक छोटा सा अंश न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अर्जित हो, न्यायालय के पास मामले में अधिकार क्षेत्र होगा। अनुच्छेद 18 में, निम्नलिखित आयोजित किया गया था: -

"18. रिट याचिका में दिए गए तथ्यों का एक संबंध होना चाहिए जिसके आधार पर प्रार्थना की जा सकती है। जिन तथ्यों का उसमें की गई प्रार्थना से कोई लेना-देना नहीं है, उन्हें कार्रवाई के कारण को जन्म देने के लिए नहीं कहा जा सकता है जो न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करेगा।

26. एक अन्य निर्णय जिस पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने भरोसा किया है, वह **नवल किशोर शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य, (2014) 9 एससीसी 329** है। उपरोक्त मामले में, याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें विकलांगता मुआवजे और आर्थिक क्षति सहित विभिन्न राहतों की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने विभिन्न राहत देने के लिए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, उन्हें शिपिंग विभाग, भारत सरकार, मुंबई द्वारा जारी आदेशों द्वारा अयोग्य घोषित किया गया था। 297 इस न्यायालय ने माना कि पटना उच्च न्यायालय के पास याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। अनुच्छेदग्राफ 17 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया था: -

"17. हमने रिट याचिका में दिए गए तथ्यों और अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों का अवलोकन किया है। निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता ने सांस लेने में कठिनाई सहित विभिन्न बीमारियों के कारण बीमारी की सूचना दी। उसे अस्पताल रेफर कर दिया गया। नतीजतन, उन्हें आगे के चिकित्सा उपचार के लिए साइन ऑफ कर दिया गया। अंत में, प्रतिवादी ने स्थायी रूप से अपीलकर्ता को पतला कार्डियोमायोपैथी (हृदय मांसपेशियों की बीमारी) के कारण समुद्री सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप, भारत

सरकार के पोत परिवहन विभाग ने 12-4-2011 को एक आदेश जारी किया जिसमें अपीलकर्ता का नाविक के रूप में पंजीकरण रद्द कर दिया गया। पत्र की एक प्रति अपीलकर्ता को बिहार में उसके मूल स्थान पर भेजी गई थी, जहां वह चिकित्सकीय रूप से अनफिट पाए जाने के बाद रह रहा था। यह आगे प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने बिहार राज्य में अपने घर से प्रतिवादी को विकलांगता मुआवजे का दावा करते हुए एक अभ्यावेदन भेजा था। उक्त अभ्यावेदन का उत्तर प्रतिवादी द्वारा दिया गया था, जिसे उसे गया, बिहार में उसके घर के पते पर संबोधित किया गया था, जिसने विकलांगता मुआवजे के लिए उसके दावे को खारिज कर दिया था। यह आगे स्पष्ट है कि जब अपीलकर्ता को हस्ताक्षर किए गए और चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया, तो वह बिहार के गया जिले में अपने घर वापस लौट आया और उसके बाद, उसने सभी दावे किए और गया में अपने घर के पते से अभ्यावेदन दायर किया और उन पत्रों और अभ्यावेदनों पर उत्तरदाताओं द्वारा विचार किया गया और जवाब दिया गया और उन अभ्यावेदनों पर निर्णय बिहार में उसके घर के पते पर उसे सूचित किया गया। बेशक, अपीलकर्ता गंभीर हृदय मांसपेशियों की बीमारी (पतला कार्डियोमायोपैथी) और सांस लेने की समस्या से पीड़ित था, जिसने उसे अपने मूल स्थान पर रहने के लिए मजबूर किया, जहां से वह अपनी विकलांगता मुआवजे के संबंध में सभी पत्राचार कर रहा था। इसलिए, प्रथम दृष्टया, सभी तथ्यों को एक साथ देखते हुए, कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा या अंश पटना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, जहां उन्हें विकलांगता मुआवजे से इनकार करने से इनकार करने का पत्र मिला।

27. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने **सरयू सिंह बनाम भारत संघ और अन्य, 2015(2) पीएलजेआर 256** में पटना उच्च न्यायालय के खंड पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया है।. उपरोक्त एक ऐसा मामला था जहां याचिकाकर्ता ने देय पेंशन लाभों का दावा किया था, जिसकी शिकायत यह थी कि उसे किया गया भुगतान कम भुगतान था। उपरोक्त संदर्भ में, अनुच्छेद 63, 64 और 66 में खंड पीठ ने निम्नलिखित निर्धारित किया: -

"**63.** हाल ही में *नवल किशोर शर्मा बनाम भारत संघ* (2014) 9 एससीसी 329 में रिपोर्ट किया गया मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर इशारा किया कि यह प्रश्न, कि कार्रवाई का कारण, पूर्ण या आंशिक रूप से, किसी भी उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय सीमा के भीतर उत्पन्न हुआ है या नहीं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही की प्रकृति और

चरित्र के प्रकाश में तय किया जाना चाहिए। एक रिट याचिका को बनाए रखने के लिए, याचिकाकर्ता को यह स्थापित करना होगा कि उसके द्वारा दावा किए गए कानूनी अधिकार का उत्तरदाताओं द्वारा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा के भीतर उल्लंघन किया गया है।

64. कानून की स्थिति की पृष्ठभूमि में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि रिट याचिकाकर्ता, कोल इंडिया लिमिटेड का कर्मचारी था और उसके रोजगार के नियमों और शर्तों के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता, एक कर्मचारी के रूप में, पटना में अपने नियोक्ता द्वारा अपने पेंशन और पेंशन लाभों का भुगतान करने की आवश्यकता है। 66. यदि, इसलिए, रिट याचिकाकर्ता को पटना में पेंशन और पेंशन लाभ के रूप में देय और देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पटना में देय और देय पेंशन और पेंशनरी लाभ प्राप्त करने के उसके अधिकार से वंचित किया जा रहा है; नतीजतन उनके अधिकार का उल्लंघन या चोट का कष्ट पटना में है।

28. उसी उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रासंगिक था, जो निर्णय हालांकि समय से पहले दिया गया था, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया था।

29. वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, हम इस सुविचारित राय के हैं कि कार्रवाई के कारण का हिस्सा पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है। मृतक याचिकाकर्ता भारतीय स्टेट बैंक, दरभंगा में अपने बचत बैंक खाते में पिछले 08 वर्षों से लगातार पेंशन प्राप्त कर रहा था। स्वर्गीय बीएन मिश्रा की पेंशन रोके जाने से वह अपने पैतृक स्थान पर प्रभावित हुए, उन्हें पेंशन के लाभ से वंचित किया गया जो उन्हें अपने नियोक्ता से मिल रहा था। नियोक्ता को एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को उस स्थान को इंगित करने की आवश्यकता होती है जहां वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त करेगा। स्वर्गीय श्री बीएन मिश्रा ने भारतीय स्टेट बैंक, दरभगा, बिहार के राज्य में अपनी पेंशन प्राप्त करने का विकल्प चुना था, जो उनका मूल स्थान था, जहां से वह पिछले 08 वर्षों से नियमित रूप से अपनी पेंशन ले रहे थे, पेंशन के रुकने से कार्रवाई का कारण बना, जो उस स्थान पर उत्पन्न हुआ जहां याचिकाकर्ता लगातार पेंशन प्राप्त कर रहा था। इस प्रकार, हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ का यह

विचार कि रिट याचिका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर सुनवाई योग्य नहीं है, पूरी तरह से गलत था और इससे याचिकाकर्ता को बहुत कठिनाई हुई है।

30. एक और सबमिशन जो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान वकील द्वारा आगे बढ़ाया गया है, वह यह है कि रिट याचिका को अदालत गैर संयोजक के सिद्धांत पर सही तरीके से खारिज कर दिया गया था। अदालत गैर संयोजक को पी. रामनाथ अय्यर, एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन, तीसरे संस्करण द्वारा निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है: -

"सिद्धांत है कि एक मामले को उस स्थान की अदालत में सुना जाना चाहिए जहां पक्ष, गवाह और साक्ष्य मुख्य रूप से स्थित हैं।

31. ब्लैक लॉ डिक्शनरी निम्नलिखित शब्दों में फोरम संयोजक को परिभाषित करती है: - "अदालत जिसमें एक कार्रवाई सबसे उचित रूप से लाई जाती है, पार्टियों और गवाहों के सर्वोत्तम हितों और सुविधा को ध्यान में रखते हुए।

32. कुसुम **सिल्ली एवं मिश्र धातु** लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय ने फोरम संयोजकों के सिद्धांत का भी उल्लेख किया है। अनुच्छेद 30 में निम्नलिखित कहा गया था: -

"फोरम 30 बुलाता है। हालांकि, हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि भले ही कार्रवाई के कारण का एक छोटा सा हिस्सा उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है, लेकिन उच्च न्यायालय को योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए मजबूर करने वाला एक निर्धारक कारक नहीं माना जा सकता है। उपयुक्त मामलों में, न्यायालय फोरम संयोजकों के सिद्धांत को लागू करके अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। [देखें *भगत सिंह बुग्गा बनाम दीवान जगबीर साहनी* [एआईआर 1941 कैल 670], मदनलाल जालंव। मदनलाल [एआईआर 1949 कैल 495], *भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम झरिया टॉकीज एवं कोल्ड स्टोरेज (पी) लिमिटेड* [1997 सीडब्ल्यूएन 122], *एसएस जैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ* [(1994) 1 सीएचएन 445] और *न्यू होराइजन्स लिमिटेड बनाम भारत संघ* [एआईआर 1994 डेल 126]।

300 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2020] 12 एससीआर 33. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता को झारखंड उच्च

न्यायालय में रिट याचिका दायर करनी चाहिए थी जहां उसकी पिछली रिट याचिका लंबित थी। पिछली रिट याचिका जो शुरू में 2006 में पटना उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, ऊपर उल्लिखित राशि की वापसी के लिए थी। पटना उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर रिट याचिका खारिज करने के बाद, श्री बीएन मिश्रा ने राहत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में 2013 की रिट याचिका संख्या 4930 दायर की थी, जिसका दावा 2006 की रिट याचिका संख्या 13955 में किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 दायर करने की कार्रवाई का कारण पूरी तरह से अलग था। पेंशन रोकने और 08 लाख रुपये से अधिक की राशि वापस मांगने से याचिकाकर्ता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जो अपने मूल स्थान दरभंगा में रह रहा था। पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी को रिट याचिका दायर करने के लिए किसी अन्य न्यायालय में जाने के लिए नहीं कहा जा सकता है, जब उसके पास पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण हो। एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए सुविधा उस स्थान पर अपने मामले पर मुकदमा चलाना है जहां वह था और पेंशन प्राप्त कर रहा था। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति में कोई सार नहीं है।

34. परिणामस्वरूप, हम अपील की अनुमति देते हैं, पटना उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं और मानते हैं कि 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 पटना उच्च न्यायालय में पूरी तरह से बनाए रखने योग्य थी और विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने में त्रुटि की थी। पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को पुनर्जीवित किया गया है।

35. हमारा यह भी विचार है कि अपीलकर्ता अपने निर्वाह के लिए रिट याचिका में अंतरिम आदेश की हकदार है। अपीलकर्ता के पति, जिन्होंने रिट याचिका दायर की थी, की रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद, अपीलकर्ता, विधवा को प्रतिस्थापित किया गया था। पेंशन रोके जाने पर सवाल उठाते हुए रिट याचिका दायर किए छह साल बीत चुके हैं। अपीलकर्ता विधवा होने के नाते अपने निर्वाह के लिए पेंशन लाभ की भी हकदार है क्योंकि उसका पति पेंशन प्राप्त कर रहा था। हमारा विचार है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता अनंतिम पेंशन का भुगतान करने का हकदार है जो रिट याचिका में अंतिम निर्णय के अधीन होगा। इसलिए, हम प्रतिवादी संख्या

4 से 8 को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को अनंतिम पेंशन का भुगतान दिसंबर, 2020 के महीने से किया जाए, जो रिट याचिका में पारित अंतिम आदेशों के अधीन होगा। तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।

अंकित ज्ञान अपील की अनुमति

यह अनुवाद तलत परवीन, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।